

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2000
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक)

राष्ट्रीय बेरोजगारी दर

2000. श्री इमरान प्रतापगढ़ी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयु-वर्ग, महिला-पुरुष और क्षेत्र-वार ब्यौरे सहित राष्ट्रीय बेरोजगारी दर के वर्तमान आंकड़े क्या हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार बेरोजगारी की दर क्या रही है;
(ग) बढ़ती बेरोजगारी दर से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) पिछले वर्ष किन-किन क्षेत्रों में रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और किन-किन क्षेत्रों में गिरावट आई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लिए सामान्य स्थिति पर आयु वर्ग द्वारा व्यक्तियों के अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई तालिका के निम्नानुसार है:

आयु वर्ग	वर्ष
15-29 वर्ष	10
15-59 वर्ष	3.4
15 वर्ष और उससे अधिक	3.2

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए लिंग और क्षेत्र द्वारा सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे तालिका के निम्नानुसार हैं:

लिंग	यूआर (% में)
पुरुष	3.3
महिला	2.9

क्षेत्र	यूआर (% में)
ग्रामीण	2.4
शहरी	5.4

इसके अतिरिक्त, नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2017-18 से 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) में नीचे दी गई तालिका के अनुसार घटती प्रवृत्ति है:

वर्ष	यूआर (% में)
2017-18	6.0
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2
2021-22	4.1
2022-23	3.2

स्रोत: पीएलएफएस

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित के.एल.ई.एम.एस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्रीयाँ और एस: सेवाएँ) डेटाबेस, अखिल भारतीय स्तर पर, रोजगार अनुमानों को प्रदान करता है। डेटाबेस की न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान में देश में रोजगार वर्ष 2022-23 में 59.67 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है। 2022-23 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 4.67 करोड़ है। आरबीआई द्वारा वर्ष 2022-23 तक सृजित क्षेत्रवार रोजगार जारी किया जाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहती है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और अवसरों की प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की है।
